











# सम्पादकीय

## अनिश्चितता से घिरी अर्थव्यवस्था

वैशिक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल और अस्थिरता का रुख बना हुआ है। इस कारण आर्थिक वृद्धि के अनुमान भी प्रभावित हो रहे हैं। बीते दिनों कई संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाया है। इस साल के लिए ये अनुमान उतने नहीं घटाए गए, जितने अगले साल के लिए। यह दर्शाता है कि बदलते वैशिक घटनाक्रम का प्रभाव अगले साल को और अनिविच्छिन्न बनाने जा रहा है। भारत के नजरिये से यही सकारात्मक है कि यहां स्थिति उतनी बुरी नहीं है। यही कारण है कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए 6.5 प्रतिशत से सात प्रतिशत का अनुमान अभी भी कायम है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊँची वृद्धि दर है। वृद्धि के अनुमानों में बार-बार संशोधन-परिवर्तन दर्शाता है कि स्थितियां कितनी विकट हो चली हैं। अर्थव्यवस्था कब दिशा बदलकर अपनी दशा बदलेगी, यह कह पाना मुश्किल हो रहा है। महागाई ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, जिससे निपटने के लिए कठिनी बैक ब्याज दरें बढ़ाने में लगे हैं। पता नहीं महंगाई पर इससे कितना अंकुश लग पार हाँ है, मगर आर्थिक गतिविधियां जरूर प्रभावित हो रही हैं। अर्थव्यवस्था में अनुमानों के बदलावों को लेकर अनेक विवाद हो रहे हैं। यह अनुमानों के बदलावों को लेकर अनेक विवाद हो रहे हैं।

विश्व लगभग हर वर्ष और हर में कहीं न कहीं लोगों का किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन चलता ही रहता है। जैसे इरान में महिलाओं ने जो आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा हुआ है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सनाई दे रही है। हालांकि ऐसे मौजूदा समय में इरान में महिलाओं का प्रमुख नारा तुमें लाइफ फ्रीडम है। अपने बालों को काटना और हिजाब या बुर्का की होली जलाना इन महिलाओं के आंदोलन की पहचान बनाया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरों की बात कर तो

पर उत्तर आए थे। बीते 29 मई, 2020 को अमेरिका के मिसेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में श्वेत पुलिसकर्मीयों द्वारा एक अश्वेत नागरिक जार्ज फ्लायट की बर्बर हत्या के विरोध में इस आंदोलन की शुरूआत हुई थी। इंगलैंड के

ने पुलिस की कार्यप्रणाली में सूधार के कानूनों पर विचार शुरू कर दिया गया था। अमेरिका में गर्भपात का अधिकार पाने के लिए महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं। अमेरिका में दशकों से ये मुद्दा ज्यों का त्यों बना हआ है। अमेरिका में

की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी थीं। उनका कहना था कि महिला इस संबंध में क्या फैसला ले इसका हम उन्हें दिया जाना चाहिए। अमेरिका में हुए इसके आंदोलन को विश्व के कई हिस्सों से समर्थन भी मिला था। आपको

रहा। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस आंदोलन के बारे में कहा गया था कि एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ विश्व बिरादरी की इसके प्रति सोचा। ये आंदोलन अमेरिका द्वारा छेड़े गए युद्ध के खिलाफ था। आंदोलनकारी



इस आंदोलन के दौरान करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। अमेरिका में जार्ज फ्लायट की हत्या के बाद शुरू हुआ लैंड्रैक लाइव्स मैटर आंदोलन को गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। 25 मई 2020 की एक घटना के बाद ये आंदोलन पूरे अमेरिका में फैल गया और विदेशों में भी इसके समर्थन में लोग सङ्कड़ों

ब्रिस्टल शहर में 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कोलस्टन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं अमेरिका और उसके बाहर कई जगहों पर हुई थीं। जार्ज की हत्या के बाद अफ्रीकी अमेरिकन लोग सँझियों पर उतरे थे। अमेरिका के कई दिग्मज और जाने माने चौहरे भी इस आंदोलन का गवाह बने थे। इस घटना से सबक लेकर अमेरिका के कई राज्यों और नगरपालिकाओं

ये विवाद 1973 में शुरू हुआ था। उस वक़्त देश की सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर लिया था। कोर्ट का कहना था कि ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है। 1992 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई महिला गर्भपात को लेकर अपना फैसला खुद ले सकती है। इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। इसी वर्ष जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटा तो हजारों बता दें कि विश्व के कई देशों में गर्भपात के खिलाफ नियम हैं। वहां पर गर्भपात कराए जाने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वर्ष 2002 के अंत में इराक युद्ध के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही एक आंदोलन की शक्ति ले ली थी। ये आंदोलन जल्द ही बड़े स्तर पर चला गया और इसके समर्थन में विश्व के कई देशों में लोग सङ्कोच पर उतरे। 2003 में भी ये जारी

आतंकवाद को सहने की आदत, कई बार अदालतों का ऐसा रखेया चिंताजनक

बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर के एक पाकिस्तानी आतंकी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्वयं को सुनाई गई फांसी की सजा पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। मुहम्मद आरिफ उफे अशफाक को दिसंबर 2020 में लाल किले में तैनात सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट पर हमले का दोषी पाया गया था। इस हमले में आतंकियों की गोलीबारी में सेना के तीन जवान बलिदान हुए थे। यह तो राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी की मौत की सजा बरकरार रखी, लेकिन यह जानना निराशाजनक है कि किसी को नहीं पता कि उसे सुनाई गई सजा पर अमल कब होगा। इस आतंकी को

अक्टूबर 2005 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई, फिर 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी। मृत्युदंड पाए इस आतंकी ने इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की। यह याचिका भी 2012 में खारिज कर दी गई। इसके उपरांत उसने क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक याचिका दायर की। जनवरी 2014 में यह भी खारिज हो गई। पता नहीं अब यह आतंकी क्या करेगा, लेकिन उसके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार तो है ही। वह इस अधिकार का उपयोग चाहे जब करे, 2014 के बाद से अब तक उसे फासी देने का कोई उपक्रम न किया जाना यही

A black silhouette of a person holding a rifle, standing against a background of a cloudy sky. The person appears to be wearing a head covering. The rifle is held vertically, with the barrel pointing upwards.

दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि अमुक मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइ को सौंपी गई। यह भी कोई नई अनोखी बात नहीं कि देश के विभिन्न हिस्सों से कभी अल्कायदा, कभी इस्लामिक स्टेट और कभी किसी अन्य आतंकी संगठन के सदस्य इस जांच एजेंसी की गिरफ्त में आते रहते हैं। आतंकवाद का खतरा किस तरह सिर उठाए हुए है, इसका पता इससे चलता है कि रह-रहकर किसी न किसी आतंकी हमले के थड़यत्र का भंडाफोड़ होता रहता है। ऐसा ही एक भंडाफोड़ दीपावली की पूर्व संध्या यानी 23 अक्टूबर को कोयबद्दूर में तब हुआ, जब संगमेश्वर मंदिर के पास से गुजर रही कार में एक भीषण धमाका हआ। इस धमाके

में कार चालक जमीशा मुबीन मारा गया। जांच में पता चला कि मुबीन का उद्देश्य मंदिर में आत्मघाती धमाका करना था, लेकिन किसी गफलत के कारण समय से पहले कार में विस्फोट हो गया और वह बैमौत मारा गया। पहले यह माना जा रहा था कि मुबीन ने इस हमले की साजिश स्वयं ही रची और उसका किसी आतंकी संगठन से संबंध नहीं था, लेकिन एनआई की जांच में पता चला कि उसके कई और साथी इस साजिश में शामिल थे। इनमें से छह को गिरफतार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ में पता चला कि पूरे दक्षिण भारत में आतंकी हमले करने का तैयारी थी। मुबीन एक झंजीनियर था और वह काँड़ सम्पर्य पहले भी

पुलिस की निगाह में आया था। पुलिस को संदेह था कि वह इस्लामिक स्टेट की एक स्थनीय शाखा बनाना चाहता था। उससे पूछताह भी हुई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसके मारे जाने के बाद जब एनआइए ने उसके घर जाकर भानबीन की तो उसे तमाम जिहादी साहित्य मिला, जिसमें जिहादी हरकतों को फर्ज बताया गया था। इसके अलावा बम बनाने की सामग्री, जिहादी बातों से भरी एक डायरी और 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में आतंकी धमाके कराने वाले एक जिहादी के 40 वीडियो भी मिले। इन वीडियो में जिहादी हमलों की वकालत की गई थी। इसी तरह के 15 वीडियो जाकिर नाइक के मिले।

# अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आरोपों को अभिव्यक्ति के हन-

A photograph showing a large, modern building complex at night. The building has multiple stories and is illuminated from within, with lights visible through the windows. In the foreground, there are some trees and bushes. The overall atmosphere is dark, suggesting it's nighttime.

A photograph of the Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India, set against a clear blue sky. The building features traditional Indian architectural elements like red sandstone walls and white domes.

‘सिर तन से जुदा’ नारों के साथ होने वाली राष्ट्रव्यापी हिंसा दिखाई नहीं देती? क्या उसे दर्जनों हिंदू-युवक-युवतियों या कार्यकर्ताओं की निरंतर हो रही हत्याएं नहीं दिख रहीं? यह भी अचरज की बात है कि राज्यों को स्वतः संज्ञान लेने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने नामपली की उस निचली अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसने अकबरखुदीन औरैसी को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया था। एआइएमआइएम नेता अकबरखुदीन ने ‘15 मिनट पुलिस हट जाने की सूरत में हिंदूओं का बुरा हाल करने’ की धमकी दी थी। निःसंदेह पिछले कुछ वर्षों में भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जनसंभाषण में तल्खी बढ़ी है। इसके साथ ही इस्लामी कट्टरता और इस्लाम पर बोकाक चर्चा शुरू हुई है। यह विचारणीय है कि इसके लिए बढ़ती इस्लामी कट्टरता स्वयं कितनी जिम्मेदार है? एक परिपक्व व्यवस्था और स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी धार्मिक, नस्लीय, जातीय और लैंगिक समूहों को लक्ष्य कर द्वेषपूर्ण एवं हिंसा भड़काने वाले भाषण पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि मजहबी और राजनीतिक विचारधारा द्वारा जनित विकारों पर निर्भीक संवाद की गुजारीश बनी रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक तथ्य और मजहबी सिद्धांतों का उल्लेख किसी को ठेस पहुंचने या भावनाएं भड़कने का भय बताकर निषेध नहीं किया जा सकता। तब समस्या

भावनाएं आहत होने वाले की हैं, तथ्यों का उद्धरण देने वाले की नहीं। इस दृष्टि से पत्रकार अमीश देवगन द्वारा खाजा मोहनुद्दीन चिश्ती के शिहाबुद्दीन गोरी की लुटेरी फौज का सिपाही होने की बात या केरल के ईसाई पादरी फादर एंथनी थरे कफ़डविल द्वारा हलाल के बहिकार और इस्लाम के पैगंबर के जीवन प्रसंग का उद्धरण करने पर की गई हेट स्पीच कार्रवाई कानून का दुरुपयोग एवं व्यवस्था की ज्यादती है। सरकारों और न्यायालिका को चाहिए कि वे हेट स्पीच आरोपों को अभिव्यक्ति के हनन करने का जरिया न बनने दें। इस्लामी कङ्डरता और उसकी मजहबी प्रेरणाओं पर चर्चा को रोकने के लिए इस्लामोफेबिया नामक शब्दावली का अननवश्यक प्रयोग हुआ है। स्वतंत्र विमर्श के लिए प्रतिबद्ध बुद्धिजीवियों को देखना होगा कि इस्लामोफेबिया की तर्ज पर हेट स्पीच शब्दावली का उपयोग भी कहीं कङ्डरता विरोधी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए तो नहीं हो रहा है? न्यायालयों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और पृष्ठात्मक अभिव्यक्ति के बीच भेद को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर मामलों का संज्ञान लें। वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करते समय बड़ी से बड़ी और उग्र से उग्र भीड़ के दबाव में न आएं, अन्यथा हम लोकतंत्र न होकर भीड़तंत्र ही होंगे।

**संक्षिप्त समाचार**  
विदेश सचिव क्वात्रा  
ने न्यूयार्क में संयुक्त  
राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस  
से की मुलाकात

न्यूयार्क। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और गम्भीर मुद्दों पर चर्चा की गई। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के हवाले से दी गई। गम्भीर मुद्दों पर हुई चर्चा संयुक्त राष्ट्र में भारत के आधिकारिक विवर हैं जो दृवीट किया, विदेश सचिव महासचिव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने गम्भीर चिंता के मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनेस्को) में अपनी ओर विदेश सचिव ने वैश्विक समुदाय से समूहिक रूप से उन लोगों को बाहर निकालने का आग्रह किया जो अमेरिकी प्रतिबंध शासन सहित आतंकवादियों का बाबा बन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अकेले के अन्तिम सप्ताह में भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर थे जहाँ उन्होंने बहुपक्षवाद में वैश्विक चिंताओं और खौफनीयों पर अपने विचार व्यक्त किए। हमें भारत पर करना चाहिए भरोसा। गुटेरेस इस अवसर पर बोलते हुए, गुटेरेस ने कहा, हमें भारत पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि यह अपने इतिहास, सकृदानि और इसके संस्करण में पूरी तरह से स्थिरता के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए 20 सालों की रुक्मिणी तरह से करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत को आगामी 20 सालों की अध्यक्षता करने के लिए बढ़ाई दी और कहा कि 20 दोस्रों का वैश्विक प्रगतिहास ऐसू उत्सर्जन का 80 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत का भी प्रतिनिधित्व करता है।

## शराब पीनेवालों से भर रहीं बिहार की जेलें, नीतीश कुमार बोले- बेचने वालों पर अधिक ध्यान दे पुलिस

(आधुनिक समाचार सेवा)

पटना। शराब पीने वालों की अपेक्षा शराब के अंधेबाजों को पकड़ना अब पुलिस-प्रशासन की प्राथमिकता हो गई। अवृद्धर माह में शराबबंदी कानून के तहत 20 हजार लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। इनमें 350 डाक्टर, इंजीनियर, सरकारी सेवक और जनप्रतिनिधि हैं। जनवरी से ही विशेष अभियान चलाकर राज्य के बाहर से भी गिरफ्तारी हो रही है। शराब तकर्कों को पांच से दस साल तक की सजा सुनाई गई है। मध्य निषेध के आड़ी अमृत राज ने बताया कि सिर्फ इस साल 60 हजार लोगों को शराबबंदी कानून के तहत पकड़ा गया है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर भी चोट की गयी। राज्य में हरियाणा, पंजाब, अरण्याचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक शराब आ रही है, जहाँ से इस साल 90 शराब तकर्कों को पकड़ा गया है। अब बड़े शराब माफिया और तकर्कों की गिरफ्तारी के साथ जब पीने वालों को जुर्माना देकर छोड़ा जाएगा।



नीतीश कुमार ने सोमवार को मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के पाठक ने कहा कि शराब की सफलता नें उस्तुत क्षस्त करने पर फोकस किया जाएगा। अप्रैल में शराबबंदी समोदर्धन के बाद जब पीने वालों को जुर्माना देकर छोड़ा जाएगा।

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

## निर्भया से ज्यादा दरिंदगी हुई थी छावल की युवती के साथ

(आधुनिक समाचार सेवा)

छावल की रहने वाली 19 वर्षीय युवती को आज एक छावली के बाबत समूहिक दुर्दण के बीच बदलाव से इनकार किया गया है। यह छावली के बाबत निर्देश दिए जाएंगे। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। शराब बेचने वालों पर होगी सख्ती समीक्षा बेठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुब्रह्माणी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब

बदलाव से इनकार किया। मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मध्य सचिव के बाद अफसरों को इस बाबत निर्द

